



# भारत का राजापत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

HS  
6/3/89

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 130]

मई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 16, 1989/फाल्गुन 25, 1910

No. 130]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1989/PHALGUNA 25, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे इक उपर अलग संकालन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

विधि श्रीराम्य भंडारण

(विधायी विभाग)

प्रधिसूचना

मई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का. आ. 194(अ) -- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित  
प्रादेश भर्त्ताभारण की आनंदारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

राष्ट्रपति ने, विहार राज्य की विधान गभा के पर्व सदस्य थी फैयाजुल  
भाजम को, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 की धारा 8क की उप-  
धारा (3) के लिंगानों के प्रनुगार, निवासित आयोग द्वारा दी गई संघ के  
आधार पर, उस प्रधिनियम की धारा 6क की उपस्थाग (i) के अधीन  
नारीश 17 जुलाई, 1984 से 4 वर्ष की अवधि के लिए तारीख 26  
जनवरी, 1985 के अपने प्रादेश द्वारा निर्दित कर दिया था।

और श्री फैयाजुल भाजम से अपने मानसे के दुर्विसेषम और गान्धी-  
पति के पूर्वोक्त भावेश के अधीन स्वयं द्वारा उपरात निर्धारित के अपर्याप्ति  
भाग को रद्द करने के लिए उस विधिनियम की धारा 6क के अधीन यथा  
सातप्रिय भर्जी तारीख 18 फरवरी, 1988 की राष्ट्रपति द्वारा काइद  
की थी।

और निवासित आयोग की राय (उपायदेवें) है कि श्री फैयाजुल  
भाजम की उक्त भर्जी लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 के किसी  
उपरात के अधीन समर्पित नहीं है परिणामतः वह अवधीकार प्रिय जामे  
योग है,

गत: भारत के राष्ट्रपति ने हैमियन से ६, आर वेकटरामन उपरा-  
त्ती अस्वीकार करता है।

मार. वेकटरामन,  
भारत के राष्ट्रपति

मई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

### भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समकाल

1988 के संबंध मामला सं. 1 (लो. प्र. अधि.)

[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

**संदर्भ :** बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री फैयाजुल आजम, की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन अपनी निरहंता के रह किए जाने/पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रपति को अर्जी।

#### राय

1.1 राष्ट्रपति ने, बिहार राज्य की विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री फैयाजुल आजम को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपचारा (3) के निर्वाचनों के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय के आधार पर, 'उच्च अधिनियम की धारा 8क की उपचारा (1) के अधीन, तारीख 17 जुलाई, 1984 से, अर्थात् 1979 की सिविल इफिल सं. 3911 में उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से, 4 वर्ष की अवधि के लिए, तारीख 28 जनवरी, 1985 के अपने आदेश द्वारा, निरहंत कर दिया था।

1.2 श्री फैयाजुल आजम ने, अपने मामले में पुनर्विलोकन और राष्ट्रपति के पुर्वोक्त आदेश के अधीन स्वयं द्वारा उपगत निरहंता के अर्पण-वसित भाग के रह किए जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन यथा तात्पर्यत वर्तमान अर्जी, तारीख 16 फरवरी, 1988 को राष्ट्रपति के समकाल काइस की है। राष्ट्रपति ने, आयोग को यथा जानने के लिए उक्त अर्जी आमोग को निर्देशित की है।

2.1 मेरी राय में, वर्तमान अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी भी उपचार के अधीन कायम रखे जाने योग्य नहीं है। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा तारीख 6 अगस्त, 1975 से यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपचारा (1) के अधीन राष्ट्रपति को यह विनियित करना है कि निर्वाचन अर्जी में उच्च न्यायालय या निर्वाचन अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन में अल्प आवरण के लिए, दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने निरहंत किया जाना चाहिए या नहीं और यदि किया जाना चाहिए तो किसी कालावधि के लिए। ऐसा विनियित करते समय राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क (3) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेंगे और आयोग द्वारा दी गई राय के अनुसार कार्य करेंगे। उक्त धारा 8क (1) के अधीन राष्ट्रपति का विनियोग वंतिम है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा कोई उपचार नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रपति के विनियोग के विरुद्ध, राष्ट्रपति सहत किसी प्राधिकारी के समय अपील की जा सकती हो या उसका पुनर्विलोकन कराया जा सकता हो। उक्त धारा 8क, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अध्याय 3 में समाविष्ट है और इस मंबंध में यह उल्लेख करना सुनियत होगा कि इस अध्याय के अधीन निरहंता की किसी अवधि को रह या कम करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन आयोग की अध्यारोही प्रक्रिया, उक्त धारा 8क के अधीन आने वाली विरहंताओं से भिन्न निरहंता के अवधिकृत अपावाद के कारण, सीमित है। यथापि उक्त अधिनियम की धारा 8क (2) के अधीन, धारा 8क, जैसी कि यह डायर निर्दिष्ट निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के ठीक पूर्व थी, के अधीन उपगत निरहंत की अवधि को राष्ट्रपति द्वारा रह या कम कर दिए जाने के लिए उपर्युक्त किया गया था, तथापि ऊपर निर्दिष्ट संशोधन अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के पश्चात, धारा 8क (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निरहंत व्यक्ति के भाग में कोई उपचार नहीं किया गया है। अतः धारा 8क (2) के उपर्युक्त, उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन निरहंत के भाग में लागू नहीं होते।

2.2 उपरोक्त विधिक नियति को दृटे हृ, ५ दंड, १८ दिसंबर 1981 की एक अर्जी में, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बलवान सिंह द्वारा राष्ट्रपति को दी गई थी, राष्ट्रपति को तारीख 6 अप्रैल, 1981 की दी गई राय में यह अभिनिधारित किया था कि, श्री बलवान सिंह की अर्जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के विसी उपचार के अधीन कायम रखी जाने योग्य नहीं है। आयोग की उक्त राय के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री बलवान सिंह को उक्त अर्जी 6 जून, 1988 को अर्वाचीन कर कर दी थी। उक्त धारा 8क (1) के अधीन निरहंत के संबंधित विधि में, आयोग द्वारा दी गई उक्त राय के पश्चात, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. उपरोक्त को छान में रखते हुए मेरी यह राय है और उपनुसार यह अभिनिधारित करता है कि श्री फैयाजुल आजम की यह अर्जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी भी उपचार के अधीन कायम रखी जाने योग्य नहीं है। अतः वह अस्वीकार किए जाने योग्य है। राष्ट्रपति से प्राप्त यह निर्देश, उपरोक्त आदेश की मेरी राय के कायम उनको वापस किया जाता है।

आर. वी. एस. पेरिशास्त्री, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग  
नई दिल्ली,

[फा. म. 7 (24)/84-वि -II]  
सं. 28 दिसंबर, 1988 एम. के. रामस्वामी, संयुक्त दिविय

### MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1989

S.O. 194 (E) :—The following Order made by the President is published for general information :—

#### ORDER

Whereas Shri Faiyazul Azam, a former Member of the Legislative Assembly of the State of Bihar was disqualified by the President by his Order dated the 28th January, 1985, under sub-section (i) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951, for a period of 4 years from the 17<sup>th</sup> July, 1984, on the opinion tendered by the Election Commission in terms of sub-section (3) of Section 8A of the said Act;

And whereas Shri Faiyazul Azam a petition dated the 18th February, 1988, before the President purporting to be under Section 8A of the said Act for review of his case and removal of the unexpired portion of disqualification incurred by him under the aforesaid Order of the President;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that the said petition of Shri Faiyazul Azam is not maintainable under any provision of the Representation of the People Act, 1951, and that it is, therefore, liable to be rejected:

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, do hereby reject the said petition.

R. VENKATARAMAN,  
President of India

New Delhi, 6th March, 1989.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Before the Election Commission of India  
Reference Case No. I (RPA) of 1988

[Reference from the President under section 8A (3) of the Representation of the People Act, 1951]

In re : Petition of Shri Faiyazul Azam, a former member of Bihar Legislative Assembly to the President for removal/review of his disqualification under section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

**OPINION**

1.1 Shri Faiyazul Azam, a former member of Bihar Legislative Assembly, was disqualified by the President by his order dated 28th January, 1985, under Section 8A (1) of the Representation of the People Act, 1951 for a period of 4 years from 17th July, 1984, i.e., from the date of the Supreme Court's order in Civil Appeal No. 3011 of 1979, on the opinion rendered by the Commission in terms of Section 8A(3) of the said Act.

1.2 The present petition dated 18-2-1988 has been filed by Shri Faiyazul Azam before the President purporting to be under section 8A of the Said Act for review of his case and removal of the unexpired portion of the period of disqualification incurred by him under the aforesaid order of the President. The said petition has been referred by the President to the Commission for its opinion.

2.1 In my opinion, the present petition is not maintainable under any provisions of the Representation of the People Act, 1951. Under Section 8A of the said Act as amended by the Election Laws (Amendment) Act, 1975, w. e. f. 6th August, 1975, the President is to decide under sub-section (1) of that section whether a person found guilty of corrupt practice at an election by a High Court in an election petition or by the Supreme Court in an election appeal should be disqualified and, if so, for what period. While so deciding, he shall obtain the opinion of the Election Commission under Section 8A (3) of the said Act and shall act according to the opinion tendered by the Commission. The decision of the President given under the said section 8A (1) is final and there is no provision in the said Act whereunder the above decision of the President can be appealed against or reviewed by any authority in-

cluding the President. The said section 8A is included in Chapter III of the Representation of the People Act, 1951 and it may be relevant to mention in this connection that the overriding powers of the Commission under section 11 of the said Act to remove or reduce the period of any disqualification under the Chapter, are limited by reason of an express exception to disqualifications other than those under the said section 8A. Though under section 8A (2) of the said Act, a provision had been made for removal or reduction by the President of the period of disqualification incurred under section 8A, as it stood immediately before the commencement of the above-referred Election Laws (Amendment) Act, 1975, no such provision has been made in the case of a person disqualified by the President under Section 8A (1) after the commencement of the above-referred Amendment Act, 1975. The provisions of Section 8A (2), therefore, do not apply to a case of disqualification under section 8A(1) of the said Act.

2.2 In view of the above legal position, the Commission, in a similar petition made to the President by one Shri Balwan Singh, former member of Uttar Pradesh Legislative Assembly, had, in its opinion dated 6th April, 1981 tendered to the President, held that the petition of Shri Balwan Singh was not maintainable under any provisions of the Representation of the People Act, 1951. The President acting on the said opinion of the Commission had rejected the said petition of Shri Balwan Singh on 8th June, 1981. The law relating to the disqualification under the said section 8A (1) has not undergone any change after the said opinion was tendered by the Commission.

3. In view of the above, I am of the opinion, and accordingly hold, that the present petition of Shri Faiyazul Azam is not maintainable under any provisions of the Representation of the People Act, 1951 and is, therefore, liable to be rejected. The reference received from the President is returned to him with my opinion to the above effect.

R. V. S. PERI SASIRI,  
Chief Election Commissioner of India

New Delhi, the 28th December, 1988.

[F. No. 7 (24) /84-Leg. II]

M. K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

